बिहार में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज हेतु सर्वेक्षण

1370. **श्री राम देव भण्डारी:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बिहार में तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री टी॰ आर॰ बालू): (क) और (ख) जी हां। बिहार में ओ एन जी सी द्वारा निम्नलिखित सर्वेक्षण किए गए हैं:—

1. राज्य के समूचे क्षेत्र में 1956 में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण।
2. 17,597 केन्द्रों पर गुरुत्व चुम्बकीय सर्वेक्षण (1961-67 और 1978-80)
3. इसी अवधि में 5429 वर्ग मि॰ मी॰ के क्षेत्र में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया।
4. भूकंपीय सर्वेक्षण (1960-65 और 1977 से आगे) 4712 एस एल के और 2426 एल के।

इन सर्वेक्षणों के आधार पर बिहार में छः अन्वेषक कूपों का भी वेधन किया गया है तथा ये सभी शुष्क घोषित किए गए।

इसके अलावा आयल इंडिया लिमिटेड ने भी इष्टतम आंकड़े प्राप्त करने के लिए सर्वेक्षण निरंतरता बनाए रखने के लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश में किए गए सर्वेक्षण के भाग के रूप में बिहार के निकटवर्ती क्षेत्रों तक के क्षेत्र में वायु चुम्बकीय सर्वेक्षण और मल्टी सेंसर सर्वेक्षण के रूप में कुछ सर्वेक्षण कार्य किया है।

Renovation of Power Generating Units

1371. SHRI ANANTA SETHI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that installation of new power stations involves problems of resource crunch, locations, long gestation periods and stringent environmental, safety norms, etc. and renovation of existing power generating units is the most cost effective and feasible solution to narrow the gap between demand and supply of power;

(b) if so, the steps taken by the Power Finance Corporation for better utilisation of the existing installed capacity through life extension of old thermal/hydro power plants and their operational efficiency improvement; and

(c) whether Government have constituted any high power Expert Committee to conduct a study in this regard; if so, the details of *its* findings?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (DR. S. VENUGOPALA CHARI): (a) Renovation & Modernisation (R&M) of existing plants is also one of the many feasible options for augmenting electricity supply but cannot substitute for all supply side measures which have to include other least cost options of addition of new capacity.

(b) and (c) The Central Electricity Authority had undertaken a study and identified 44 thermal power stations involving 20869.435 MW and 55 hydro schemes involing 9653 MW requiring R&M. The R&M schemes are taken up for implementation through loan assistance from Power Finance Corporation. Till 30.9.1996, Power Finance Corporation have sanctioned Rs. 885.94 crores for 93 R&M Schemes.

FPIs in North-Eastern States

1372. DR. B.B. DUTTA:
SHRI PARAG CHALIA:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) the details of steps being taken for development of food processing industries in North-Eastern States, particularly in West Assam;

(b) whether appropriate steps are being taken to develop the industry at small-scale/cottage level and not merely by big companies; and

(c) if so, the action taken and progress made in this regard during the last three years?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI DELIP KUMAR RAY): (a) to (c) Government have taken various steps to promote food processing industries in the country which inter alia include declaration of most food processing industries as high priority, delicensing of food processing industries except brewing and distillation of alcoholic beverages and those items reserved for small scale sector, promoting domestic/foreign/NRI investments etc. Government is also operating various Plan Schemes for promoting food processing industries in the country.

During the first four years of the Elighth Five Year Plan, financial assistance amounting to Rs. 1410.48 lakhs has been provided in respect of proposals received from the North Eastern Region. Out of this, the assistance provided in respect of proposals received from Assam amount to Rs. 752.28 lakhs.

Assistance has also been provided to the North-Eastern Regional Agricultural Marketing Corporation (NERAMAC) which is catering to the development of whole North-Eastern Region.

Most of the food processing units are in the small and medium sector.

गुजरात में "छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास" के अंतर्गत कस्बों का विकास

1373. श्री गोपाल सिंह जी॰ सोलंकी: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में छोटे तथा मझौले कस्बों के समेकित विकास हेतु कोई कार्यक्रम लागू किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि इस प्रयोजनार्थ कोई धनराशि आबंटित की गई है तो उसकी मात्रा कितनी है;

(ग) क्या सरकार के पास इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु कोई अंतर्निहित तंत्र विद्यमान है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा॰ यू॰ वेंकटेश्वरलू): (क) और (ख) जी, हां। छोटे व मझौले कस्बे के समन्वित विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजना 1979-80 से गुजरात सहित सभी राज्यों में चल रही है। यह योजना पांच लाख तक की आबादी वाले शहरों पर लागू है। इसका उद्देश्य, विकास की क्षमता वाले चुनींदा कस्बों में अवस्थापना तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार करना है, ताकि ये शहर आर्थिक विकास व रोजगार के क्षेत्रीय केन्द्रों के रूप में उभर सकें, तथा बड़े नगरों/कस्बों की ओर आबादी के जाने और रोक लगाने में मददगार बन सकें। शुरूआत से लेकर 31.3.1996 तक गुजरात के 47 कस्बे योजना में शामिल हो चुके हैं तथा उन्हें 14.28 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी जा चुकी है। राज्य सरकार से प्राप्त सुचना के अनुसार छोटे व मझौले कस्बों की समेकित विकास योजना स्कीमों पर 22.04 करोड़ रुपये मार्च, 1996 तक का कुल व्यय (केन्द्रीय अंश और राज्यअंश व संस्थागत वित्त के हिस्से से) हुआ है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिशा-निर्देशों के तहत आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰, परियोजनाओं के अनुमोदन तथा निगरानी के लिए राज्यस्तरीय अनुमोदन समितियां हैं। भारत सरकार के स्तर पर आई॰डी॰एस॰एम॰टी॰ परियोजनाओं के मूल्यांकन व निगरानी करने के लिए नगर तथा ग्राम नियोजन संगठन (टी॰सी॰पी॰ओ॰) नोडल एजेन्सी बनाया गया है।